Amrut India

November 20, 2021
Page No.05
Of New Delhi

किसान मोर्चा ने कृषि कानूनों को निरस्त करने के फैसले का स्वागत किया

नई दिल्ली। देश के करीब 40 किसान संगठनों के प्रतिनिधि समूह संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को निरस्त करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा का स्वागत किया है। उसने यह भी कहा कि एसकेएम सभी घटनाक्रमों का संज्ञान लेगा और जल्द ही बैठककर आगे के निर्णयों की घोषणा करेगा। एसकेएम ने एक बयान में कहा, ''संयुक्त किसान मोर्चा इस फैसले का स्वागत करता है। हम संसदीय प्रक्रिया के माध्यम से इस घोषणा के क्रियान्वयन की प्रतीक्षा करेंगे।'' उसने जोर देकर कहा, ''किसानों का आंदोलन सिर्फ इन काले कानूनों को निरस्त करने के लिए नहीं है, बल्कि सभी कृषि उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य की वैधानिक गारंटी देने के लिए भी है। किसानों की यह महत्वपूर्ण मांग अब भी लंबित है।'' उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले करीब एक वर्ष से अधिक समय से विवादों में घिरे तीन कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की घोषणा की और कहा कि इसके लिए संसद के आगामी सत्र में विधेयक लाया जाएगा। तीनों कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन कर रहे थे।

कृषि कानून निरस्त करने का फैसला, प्रदर्शन स्थलों पर मिठाइयां बांटी गईं

नई दिल्ली। तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त किए जाने के लिए केंद्र सरकार के फैसले की घोषणा के बाद दिल्ली के सीमावर्ती इलाकों के पास किसानों के प्रदर्शन स्थलों पर कई लोगों ने शुक्रवार को सुबह मिठाइयां बांटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन कानूनों को निरस्त करने की घोषणा गुरु नानक जयंती के अवसर पर की है। मोदी ने शुक्रवार को घोषणा की कि सरकार ने तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने का फैसला किया है और उन्होंने प्रदर्शनकारी किसानों से घर लौटने की भी अपील की। किसान इन कानूनों के खिलाफपिछले करीब एक साल से प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन कानूनों को निरस्त

ईडीआईआई को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने दी 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' की मान्यता

रवांडा के किगली में 'रवांडा इंडिया एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर' स्थापित

नई दिल्ली/अहमदाबाद (अमृत इंडिया)। एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देश की उद्यमशीलता के क्षेत्र की प्रमुख संस्था राष्ट्रीय उद्यमशीलता विकास संस्थान (एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया-ईडीआईआई) को देश के स्किलिंग ईकोसिस्टम के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' (सीओई) के रूप में मान्यता दी गई है। ईडीआईआई के महानिदेशक डॉ सुनील शुक्ला ने बताया कि इस संबंध में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा एक आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना जारी की गई है। मंत्रालय द्वारा कई मापदंडों पर संस्थान की गहन जांच के बाद दी गई मान्यता शुरू में पांच साल के लिए वैध होगी। एमएसडीई द्वारा जारी सीओई की मान्यता दिशानिर्देशों के अनुसार एक 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' एक ऐसा निकाय है, जो तेजी से उभरती टैक्नोलॉजी पर विशेष ध्यान देने के साथ विशिष्ट क्षेत्रों के लिए नेतृत्व, सर्वोत्तम अभ्यास, अनुसंधान और विकास सहायता, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करता है। इसका अर्थ है ऐसा निकाय जहां उच्चतम मानकों को बनाए रखा जाता है। ईडीआईआई को स्किलिंग ईकोसिस्टम में एक उत्कृष्टता केंद्र के रूप में

मान्यता दी गई है। यह उद्योग, शिक्षाविदों और सरकारों के साथ सहयोगात्मक तरीके से काम करने वाला वन-स्टॉप राष्ट्रीय संसाधन केंद्र है। यह नए उद्यम निर्माण और रोजगार बढ़ाने को सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण और दक्षता प्रदान करता है, उभरते कौशल अंतराल को दूर करता है और उद्योग की जरूरतों से मेल खाने वाले नवाचारों के लिए अनुसंधान करता है। ईडीआईआई के महानिदेशक डॉ सुनील शुक्ला ने कहा, 'यह बहुत गर्व की बात है कि ईडीआईआई को भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा उत्कृष्टता केंद्र के रूप में मान्यता दी गई है।

कौशल और ज्ञान भारत के लिए आर्थिक विकास और सामाजिक विकास की प्रेरक शक्ति है और बदलते वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए संस्थान ने उद्यमिता के आधार पर संपूर्ण आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए समाज के विभिन्न क्षेत्रों और वर्गों को लक्षित किया है।' शुक्ला ने बताया कि उद्योग, शिक्षाविदों और सरकारों के साथ सहयोगात्मक तरीके से काम करने वाला एक-स्टॉप राष्ट्रीय संसाधन केंद्र होने के नाते ईडीआईआई को 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' की मान्यता दी गई है। यह नया उद्यम निर्माण और रोजगार बढ़ाने को सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण और दक्षता प्रदान करता है, उभरते कौशल संबंधी अंतराल को दूर करता है और उद्योग की जरूरतों से मेल खाने वाले नवाचारों के लिए अनुसंधान करता है। रवांडा के किगली में ईडीआईआई के छठे अंतरराष्ट्रीय ईडी केंद्र की स्थापना हुई है। इंस्टीट्यूट का मकसद दुनिया को उद्यमशीलता का मार्ग देना है ताकि आर्थिक विकास की राह प्रशस्त हो सके।

रवांडा-इंडिया एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर का उद्घाटन

किगली, रवांडा में केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री श्री वी. मुरलीधरन के हाथों 15 नवंबर 2021 को हुआ। केंद्र की स्थापना एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (ईडीआईआई) द्वारा भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के साथ एक समझौते के तहत की गई है। यह ईडीआईआई द्वारा स्थापित छठा अंतरराष्ट्रीय ईडी केंद्र है। इससे पहले संस्थान ने कंबोडिया, लाओ पीडीआर, म्यांमार, वियतनाम और उज्बेकिस्तान में भी केंद्र स्थापित किए हैं। ईडीआईआई के महानिदेशक ने सेंटर के बारे में बताते हुए कहा, 'उद्यमी उत्कृष्टता के उच्चतम मानदंडों को बनाए रखने के लिए केंद्र कुशल रूप से स्थानीय उद्यमियों के बीच उद्यमशीलता की संस्कृति लाते हुए उन्हें पर्याप्त ज्ञान और अनुभव से लैस करेगा, उद्यमिता शिक्षा, प्रशिक्षण और व्यापार सलाहकार सेवाएं शुरू करेगा, नीति समर्थन और निर्माण सुनिश्चित करेगा, अधिकारियों को प्रशिक्षित करते हुए यह सुनिश्चित करेगा कि रवांडा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के उदय, पोषण और विकास के लिए एक अनुकूल व्यावसायिक वातावरण बनाया जाए।' उद्यमिता विकास गतिविधियों के निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए, संस्थान स्थानीय प्रशिक्षक-प्रेरक और व्यावसायिक परामर्शदाताओं को भी सक्षम से जोड़ेगा और राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर नीति बनाने की प्रक्रिया को प्रभावित करेगा ताकि ऐसी नीतियां बनाई जा सकें जो उद्यमियों के अनुकूल हों। रवांडा-इंडिया एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर के उद्घाटन और ईडीआईआई द्वारा सलाहकार की नियुक्ति के बाद, 16 नवंबर को किगाली में पहला न्यू एंटरप्राइज क्रिएशन प्रोग्राम शुरू किया गया था। 18 दिवसीय इस कार्यक्रम में 30 संभावित उद्यमी भाग ले रहे हैं। इसके साथ ही, रवांडा में ईडीआईआई टीम व्यवहार्य व्यापार अवसरों की पहचान में भी जुटी है और स्थानीय आवश्यकताओं और शर्तों के अनुकूल कम से कम 50 से 70 परियोजना प्रोफाइल विकसित कर रही है।